



स्वच्छता समाचार



खंड 5 | अंक 33



श्री सी. आर. पाटिल केंद्रीय मंत्री की कलम से

मलीय कचरा प्रबंधन स्थायी ग्रामीण स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण घटक है और जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छ पर्यावरण दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमें सामुदायिक भागीदारी पर लगातार ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है जहां SHG और पंचायतें, उन संदर्भ-विशिष्ट, आवश्यकता आधारित और उपयुक्त तकनीकों को अपनाती हैं जो मलीय कचरा प्रबंधन के समाधानों को व्यवहार्य, समावेशी और दीर्घकालिक बनाती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत अभिनव मलीय कचरा प्रबंधन मॉडल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 7 जनवरी 2026 को एक उपयोगी चर्चा संपन्न हुई।



श्री वी. सोमण्णा केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

SBM(G) के तहत किए जा रहे कार्यों का श्रेय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, पंचायतों और समुदायों की सामूहिक कार्रवाई को जाता है। जबकि SBM(G) के तहत हासिल की गई प्रगति सराहनीय है, फिर भी आगे का रास्ता व्यवहारवादी परिवर्तन को और अधिक बढ़ाने, संचालन एवं रखरखाव प्रणाली को मजबूत करने और स्वच्छता के नेताओं के रूप में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमें स्वच्छता कर्मचारियों और VWSC की निरंतर भागीदारी के साथ-साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नवाचार और दृढ़ता को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

1 सितंबर 2025 को SBM(G) पर गोलमेज सम्मेलन





श्री अशोक के. के. मीणा सचिव की कलम से

ग्रामीण स्वच्छता और जल क्षेत्र में किया जा रहा कार्य एक समग्र प्रयास को दर्शाता है, जहां ग्राम पंचायतें सेवा प्रदायगी का केंद्र बिंदु हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, इसका मतलब विकेंद्रीकृत, सामुदायिक नेतृत्व वाली प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो दीर्घकालिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सामंजस्य, प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्थिरता द्वारा समर्थित हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि समुदाय उन परिसंपत्ति और सेवाओं का स्वामित्व प्राप्त करें, जो समय के साथ-साथ लाभ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

26 मार्च 2026 को श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा



श्रीमती ऐश्वर्या सिंह संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा, स्वच्छता परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक कार्यशीलता सुनिश्चित करते हुए कार्यदक्ष, आत्मनिर्भर और समुदाय संचालित संचालन और रखरखाव (O&M) संबंधी प्रणालियों के माध्यम से परिणामों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गांवों के लिए ODF Plus (उत्कृष्ट) का दर्जा प्राप्त करने में हुई प्रगति, इस कार्यक्रम के तहत एक स्थायी प्रतिबद्धता बनी हुई है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।



क. कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

महीने के अंत में किया गया अवलोकन

31 मार्च 2026 तक

ODF PLUS MODEL

- ODF PLUS (उत्कृष्ट) घोषित गांव: **5 लाख से अधिक**
- गंदला जल प्रबंधन की व्यवस्था वाले संसूचित गांव: **5.4 लाख से अधिक**
- ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था वाले संसूचित गांव: **5.3 लाख से अधिक**
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों से कवर किए गए ब्लॉक: **5400**
- गोबरधन के अंतर्गत, SBM(G) के अंतर्गत **1120** सामुदायिक/क्लस्टर स्तरीय बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है।



फरवरी और मार्च 2026 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना की समीक्षा के लिए DDWS में आयोजित, नियोजित मूल्यांकन समिति (PAC) की बैठकों की झलकियां



स्वच्छता पखवाड़ा 2026 कैलेंडर के अनुसार मार्च में भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग

- i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- ii. वस्त्र मंत्रालय
- iii. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
- iv. इस्पात मंत्रालय

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय



- बोबिली के चिल्ड्रन होम में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके कला और शिल्प गतिविधियों और सुरक्षित भोजन तथा पेयजल स्वच्छता पर प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।
- रोज चिल्ड्रन होम में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- पर्यवेक्षकों/CDPO द्वारा लेह जिले में आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में समीक्षा और स्वच्छता निरीक्षण गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- थिंग्सल्यलिया ICDS परियोजना में स्वच्छता विषय पर कहानी सुनाने और चित्रकला संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- ICDS परियोजना ताइसुरु, जिला कारगिल, लद्दाख में आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में स्वच्छता का निरीक्षण किया गया।
- लिटिल वुड गर्ल्स होम में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- कचरे के पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'अपशिष्ट से अद्भुतता (वेस्ट टू वंडर)' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- लद्दाख के कारगिल जिले में ICDS प्रोजेक्ट चिकटन के तहत कहानी सुनाने का उपयोग करते हुए जागरूकता गतिविधियों और स्वच्छता संबंधी भूमिका क्रीड़ाओं का आयोजन किया गया।
- रीक ICDS परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रदर्शन आयोजित किया गया।
- वन स्टॉप सेंटर, लाहौल और स्पीति में स्वच्छता संदेशों के साथ दीवार पेंटिंग विकसित की गईं और कमरों, शौचालयों, रसोई और आस-पास के क्षेत्रों की गहन सफाई की गई।
- नगोपा ICDS परियोजना के तहत मिम्बुंग सर्कल के तहत शौचालयों और हाथ धोने के क्षेत्रों की सफाई की गई।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, माताओं की समितियों और लाभार्थियों द्वारा फैजाउ में आंगनवाड़ी परिसरों (पोषण उद्यान, फर्श, दीवारों, शौचालयों आदि) की सफाई की गई।
- फाल्हुंग 1 में आंगनवाड़ी केंद्रों में अपशिष्ट पृथक्करण और प्लास्टिक मुक्त पहल लागू की गई।
- ऐनाक आंगनवाड़ी केंद्र में अपशिष्ट पृथक्करण और स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया।



ख. मार्च 2026 में स्वच्छता पखवाडा

स्वच्छता पखवाड़े को दर्शाने वाली जमीनी स्तर की कार्टवाइ



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:
पोषण, बगीचे की दीवारों और शौचालयों सहित
आंगनवाड़ी परिसर की सफाई



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:
आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता
पर प्रदर्शन आयोजित किए गए



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: कहानी सुनाने का उपयोग करते हुए जागरूकता गतिविधियों
और स्वच्छता संबंधी भूमिका क्रीड़ाओं का आयोजन किया जा रहा है



ii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय



- स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का 31 मार्च 2026 को NER-IWALM परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- नियमित सफाई अभियान के साथ-साथ CSMRS अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई संवेदीकरण गतिविधियां आयोजित की गईं।
- गतिविधियों में कूड़े को हटाना, रास्तों की सफाई, अवांछित वनस्पतियों को साफ करना और परिसर की समग्र स्वच्छता शामिल थी।
- वृक्षारोपण गतिविधियों के साथ-साथ 'स्वच्छता और जल' विषय पर एक कार्यशाला और NERIWALM में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
- CSMRS के समिति कक्ष में सफाई अभियान चलाया गया।
- तुंगभद्रा बांध में नेताजी पार्क और उसके आस-पास सफाई गतिविधियां शुरू की गईं।
- कार्यस्थल की सफाई, पुरानी वस्तुओं/फर्नीचर के निपटान और पुरानी फाइलों की छंटाई पर केंद्रित विशेष अभियान चलाए गए।
- MTS कर्मचारियों के लिए "स्वच्छ भारत" पर निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- स्वच्छता श्रमदान HLC नंबर 2 उपखंड कार्यालय, तोरंगल्लू कॉलोनी और आस-पास के क्षेत्र में आयोजित किया गया था।
- CSMRS में गलियारों और शौचालयों की सफाई सहित स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- स्वच्छता पखवाड़ा और विश्व जल दिवस के दौरान वृक्षारोपण गतिविधियां आयोजित की गईं।

स्वच्छता पखवाड़े को दर्शाने वाली जमीनी स्तर की कार्टवाइ



जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय: NERIWALM परिसर के खुले पार्किंग क्षेत्र और पहुंच मार्ग की सफाई



iii. इस्पात मंत्रालय



- VIP गेस्ट हाउस में ME-CON द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- खनन स्थलों पर आवासीय शिविर कॉलोनीयों के पास राष्ट्रव्यापी मेगा प्लॉगिंग अभियान का आयोजन किया गया।
- स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के लिए स्वच्छता रैलियां आयोजित की गईं।
- खनन क्षेत्रों के पास के स्कूलों में डॉक्टरों द्वारा स्वच्छता सेमिनार आयोजित किए गए।
- MOIL DAV, RNT स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- CMD, निदेशकों और CVO सहित MSTC के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृक्षारोपण गतिविधियों में भाग लिया।
- A.G. बाल विकास स्कूल, सुंगी में सैनिटरी पैड के वितरण सहित मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए

स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- सुंगी गांव में बच्चों और समुदाय के लिए स्वच्छता और निबंध लेखन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर में एक सेल्फी बूथ स्थापित किया गया था।
- डॉक्टरों द्वारा कार्यस्थलों पर स्वच्छता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सामान्य स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग के हानिकारक प्रभावों को शामिल किया गया।
- प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज द्वारा एमएसटीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में स्वच्छता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

स्वच्छता पखवाड़े को दशनि वाली जमीनी स्तर की कार्टवाइड



इस्पात मंत्रालय: स्वच्छता पखवाड़े को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।



इस्पात मंत्रालय: खनन क्षेत्रों के पास के स्कूलों में डॉक्टरों द्वारा स्वच्छता सेमिनार का आयोजन किया गया।



i. श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने DDWS का दौरा किया



श्रीलंका के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता में भारत के अनुभव को समझने के लिए अपने अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में 26 मार्च को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) का दौरा किया। DDWS के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने तथा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण मजबूत सामंजस्य, प्रौद्योगिकी के उपयोग और टिकाऊ डिजाइन द्वारा समर्थन देकर ग्राम पंचायतों को जमीनी स्तर पर

प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने विकेंद्रीकृत सेवा वितरण, सामुदायिक स्वामित्व और गंदला जल प्रबंधन और संसाधनों के पुनः उपयोग के माध्यम से दीर्घकालिक स्थिरता सहित प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डाला।

JJM और SBM(G) प्रभागों द्वारा प्रस्तुतियों में ग्रामीण नल जल कवरेज में प्रगति और अपशिष्ट प्रबंधन और निरंतर व्यवहारवादी परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ ODF से ODF Plus (उत्कृष्ट) गांवों में स्वच्छता प्रयासों के परिवर्तन को शामिल किया गया। यात्रा का समापन लागत प्रभावी समाधानों पर एक संवादात्मक चर्चा के साथ हुआ, जिसमें दोनों पक्ष जल और स्वच्छता में ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए।



ii. जल महोत्सव 2026 में SBM(G) से संबंधित विषयगत सत्र



विज्ञान भवन में 11 मार्च 2026 को आयोजित जल महोत्सव 2026 में स्थायी गंदला जल प्रबंधन (GWM) से संबंधित विषयगत सत्र का नेतृत्व और संचालन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने किया। सत्र में गंदला जल प्रबंधन को स्वच्छता और जल के बीच एक प्रमुख क्रॉस-कटिंग क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो SBM(G) और जल जीवन मिशन के तहत परिणामों को एकरूपता प्रदान करता है।

इसने सिक्किम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सरपंचों सहित NMCG के विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थाओं और जमीनी स्तर के नेताओं ने भाग लिया, जिससे नीतिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ मूलभूत अनुभवों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में गंदला जल प्रबंधन के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों तक पहुंच में वृद्धि, गांव में स्वच्छता बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रोकने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया।

सत्र में परिप्रेक्ष्य में बदलाव के संबंध में भी जोर दिया गया, अर्थात् गंदला जल को न केवल अपशिष्ट के रूप में देखना, बल्कि एक ऐसे संसाधन के रूप में देखना जो भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और महत्वपूर्ण रूप से उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा देता है। SBM(G) चरण II के तहत, गंदला जल प्रबंधन ODF Plus (उत्कृष्ट) गांवों को प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग है, जिसमें पारिवारिक और सामुदायिक दोनों स्तरों पर स्थानीय रूप से उपयुक्त, कम लागत और टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सोखता गड्ढों, किचन गार्डिन, सामुदायिक प्रणाली और विकेन्द्रीकृत शोधन मॉडलों जैसे सहभागी पहलों पर प्रकाश डाला गया, जो प्रकृति-आधारित और तकनीकी दृष्टिकोणों के मिश्रण को दर्शाता है।

चर्चा में इन प्रणालियों को बनाए रखने में ग्राम पंचायतों, VWSC और समुदायों की भूमिका को रेखांकित किया गया, साथ ही आने वाले वर्षों में केवल परिसंपत्ति निर्माण पर ही नहीं बल्कि उसका निरंतर उपयोग, संचालन एवं रखरखाव और मजबूत सामुदायिक स्वामित्व की ओर परिसंपत्ति निर्माण से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

i. छत्तीसगढ़ का जोश जिला आंदोलन

'जनी ऑफ सेनिटेशन हाइजिन जोश' से एमसीबी बना छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल जिला

छत्तीसगढ़ में कई जिलों में स्वच्छता प्रवर्धन की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एमसीबी में स्वच्छता प्रवर्धन की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एमसीबी में स्वच्छता प्रवर्धन की शुरुआत हो रही है।

छत्तीसगढ़ में स्वच्छता प्रवर्धन की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एमसीबी में स्वच्छता प्रवर्धन की शुरुआत हो रही है।

ग्रामीण स्वच्छता हेतु लगातार प्रयास जारी है जहां विभिन्न जिले स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यावहारिक, जन-संचालित दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं। इनमें से एक प्रयास छत्तीसगढ़ का जोश (स्वच्छता साफ-सफाई की यात्रा)।

जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय कृषि और अनुसूचित जनजाति आंदोलन है, जो ध्यान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामवीर चार नेताम और माननीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, छत्तीसगढ़ सरकार की उपस्थिति में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान एक जमीनी स्तर की स्वच्छता पहल है जो स्वच्छता से संबंधित आदतों को सुधारने, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और स्वच्छ सार्वजनिक स्थान बनाने पर केंद्रित है।

यह अभियान मध्य प्रदेश के WaSH ऑन व्हील्स (WOW) मॉडल से लिया गया है जिसे सितंबर 2025 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के WOW मॉडल

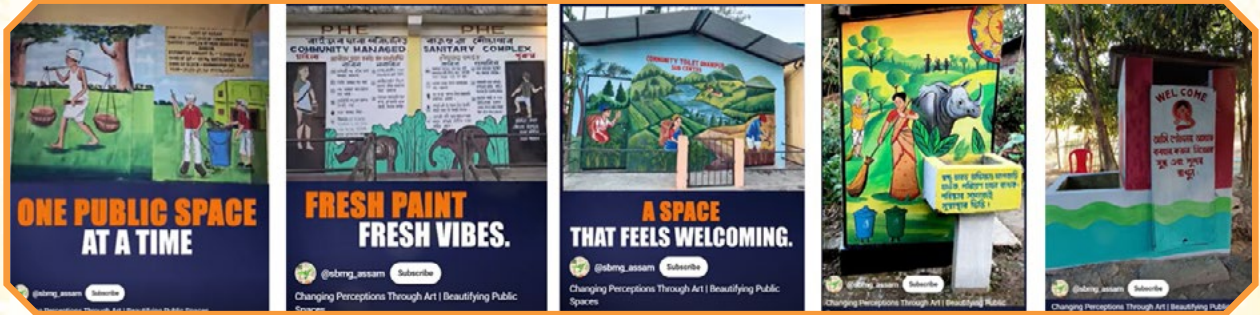
और छत्तीसगढ़ के जोश दोनों में, प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों को गरिमापूर्ण, सेवा आधारित आजीविका के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह मॉडल संस्थाओं (आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थाओं) को इन सेवाओं का लाभ उठाने और स्वच्छता कार्य के लिए भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए स्थिरता और नियमित आय सुनिश्चित होती है।

इस मॉडल का उद्देश्य पूरे जिले में स्वच्छता प्रणालियों को मजबूत करना है और यह इस कथन पर जोर देता है कि स्वच्छता केवल एक विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए सामूहिक प्रयास और जनभागीदारी की आवश्यकता है। इस अभियान के माध्यम से, अपशिष्ट के इकट्ठे होने से बचने के लिए नालियों, सड़कों, शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वच्छता केवल एक सामयिक अभ्यास नहीं है। यह अभियान स्वच्छता को सुलभ और व्यावहारिक बनाता है।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

ii. असम द्वारा स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए कला का उपयोग



पूरे असम में, SBM(G) के मिशन चमक अभियान के तहत कला का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों और स्वच्छता परिसंपत्तियों में बदलाव लाया जा रहा है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC), व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (IHHL), और यहां तक कि फ्लाईओवरों को भी भित्ति चित्रों से रंगा जा रहा है जो स्वच्छता, साफ-सफाई और गरिमा से संबंधित संदेश देते हैं। IHHL को लाभार्थियों द्वारा स्वयं उत्साहपूर्वक सजाया जा रहा है, जो स्वामित्व की भावना और "इज्जत घर" की भावना को दर्शाता है। कई जगहों पर शौचालयों को घर के अविभाज्य हिस्से के रूप में देखा जाता है।

CSC को असमिया कला रूपों, स्थानीय वस्तुओं और लोक कथाओं का उपयोग करके सुशोभित किया जाता है। कई स्थानों पर, प्रबंधन समितियों ने इन प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिन्होंने बेहतर रखरखाव और उपयोग में योगदान दिया है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, SBM(G) ने प्लास्टिक प्रदूषण, पारिवारिक अपशिष्ट पृथक्करण और सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों सहित विभिन्न विषयों पर भित्तिचित्रों और स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से फ्लाईओवरों और सार्वजनिक क्षेत्रों को सुशोभित किया। यह दृष्टिकोण रोजमर्रा की व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने के लिए दृश्य संचार का उपयोग करता है। स्थानीय रूप से प्रासंगिक कला का उपयोग इन संदेशों से समुदाय को जोड़ने में भी मदद करता है, जिससे उन्हें समझना और बनाए रखना आसान हो जाता है।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

iii. SBM(G) के तहत बिहार में सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग



altitude: 28.704423
longitude: 87.251915
elevation: 31.29+201m



ग्रामीण विकास विभाग पर अग्रणी प्रयोग प्लास्टिक कचरे से 3 जिलों में 10 किमी सड़क बनाई

कोई भी शहरको नहीं बिलकुल पुराना कचरा नहीं है। कचरा को सही ढंग से प्रबंधित करने से ही शहर स्वच्छ और आरोग्यकारी बन सकता है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत तीन नए और बेहतर सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग को अग्रणी प्रयोग के रूप में माना जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़कें न केवल सड़क बनाने में मदद करती हैं, बल्कि प्लास्टिक कचरे को प्रदूषण से दूर रखती हैं।

प्लास्टिक कचरे का प्रसंस्करण कर बनीं 10.5 किमी सड़कें

राज्य ब्यूरो, जारखण्ड • एक नवोदय युवा प्लास्टिक कचरे प्रसंस्करण कर तीन जिलों में 10.5 किलोमीटर सड़कों में सड़कें बनाई जा चुकी हैं। आगामी दिनों में अन्य जिलों में भी इस व्यवहार को लागू करने की योजना है। यह प्लास्टिक प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक कदम है।

- प्लास्टिक और सड़क**
- खाड़िया में एक टन अपशिष्ट से एक किलोमीटर सड़क बनी
 - पूर्णिया में 3.08 टन अपशिष्ट से 4.05 किलोमीटर सड़क बनी
 - औरंगाबाद में 3.5 टन अपशिष्ट से पांच किलोमीटर सड़क बनी

उपरोक्त ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनसमय बचाने के लिए है। सड़कों को अपशिष्ट मजबूत बनाना है। साथ ही प्लास्टिक कचरे का सही निपटारा करने से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।



SBM(G) के तहत बिहार में एक सामंजस्यपरक मॉडल ग्रामीण स्वच्छता और अवसंरचना से संबंधित दृष्टिकोण में बदलाव ला रहा है। पूर्णिया, खगड़िया और औरंगाबाद जैसे जिले प्लास्टिक कचरे को टिकाऊ सड़कों में बदल रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के बीच यह सहयोग न केवल प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान कर रहा है बल्कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रहा है।

बिहार में, प्लास्टिक अपशिष्ट को घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियों के माध्यम से एकत्र किया जाता है और राज्य भर में 171 प्लास्टिक अपशिष्ट इकाइयों (PWMU) में संसाधित किया जा रहा है। प्रसंस्कृत प्लास्टिक मुख्य रूप से कम घनत्व

और उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक और PET अपशिष्ट को सड़क निर्माण में उपयोग के लिए लगभग 7-10% के अनुपात में गर्म बिटुमेन के साथ मिलाया जाता है। इस पहल को तीन जिलों में कार्यान्वित किया गया है और इन जिलों में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके कुल 10-10.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके निर्मित सड़कों ने बेहतर स्थायित्व और जल की क्षति के प्रति प्रतिरोध को परिलक्षित किया है, जिससे समय के साथ रखरखाव की आवश्यकताएं कम हो गई हैं। राज्य इस मॉडल को अन्य जिलों में विस्तारित करने की योजना बना रहा है।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

iv. नवसारी के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन



नवसारी के स्कूलों में एक स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन पहल कार्यान्वित की जा रही है, जहां छात्र सक्रिय रूप से बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं, प्रारंभिक वर्षों से ही जागरूकता, भागीदारी और पर्यावरण-मानसिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। नवसारी जिले में, स्कूल यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे अपशिष्ट प्रबंधन को पॉट कंपोस्टिंग के सरल और प्रभावी दृष्टिकोण के माध्यम विद्यार्थी की रोजमर्रा की शिक्षा में समाहित किया जा सकता है।

इस प्रयास में 400 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों के 2,000 से अधिक विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। दैनिक भागीदारी के माध्यम से, विद्यार्थी जैविक अपशिष्ट को पृथक करते हुए उसके पुनर्चक्रण के मूल्य को समझने की सीख प्राप्त कर रहे हैं।

अब तक, 9,000 किलोग्राम से अधिक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा चुका है। उत्पन्न खाद का उपयोग स्कूल के बगीचों में किया जा रहा है और यह व्यवस्था विद्यार्थियों के बीच सीखने और स्वामित्व दोनों को मजबूत करता है।

तालुका कर्मचारियों द्वारा नियमित निगरानी और जिला अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रणालियां कार्यशील और प्रभावी बनी रहें।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

v. छत्तीसगढ़ में सीएससी-राजस्व सृजन के साथ एक आत्मनिर्भर मॉडल



नगर ग्राम पंचायत, बड़गांव-पुर ब्लॉक, कोरिया जिले में, सामुदायिक स्वच्छता परिषद (CSC) के लिए राजस्व सृजन के साथ एक आत्मनिर्भर मॉडल अपनाया गया है। CSC के निकट तीन व्यवसायिक परिषद बनाए गए हैं जिन्हें ग्राम पंचायत (GP) द्वारा अतिरिक्त राजस्व सृजन के लिए नीलाम किया गया था। CSC की दीवारों पर आकर्षक आईईसी पेंटिंग चित्रित की गई हैं। इसका संचालन और रखरखाव (O&M) ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किया जाता है।

इस मॉडल के तहत, ग्राम पंचायत द्वारा 3 दुकानों की नीलामी के माध्यम से 1.42 लाख रुपये एकत्र किए गए हैं। 900 रुपये (प्रति दुकान 300 रुपये) की आय की जा रही है। नीलामी राशि और मासिक किराए का उपयोग CSC के संचालन और रखरखाव के लिए किया जा रहा है। इनमें से एक दुकान स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों को बेचने के लिए एक स्वयं सहायता समूह (SHG) को दी गई है। ग्राम पंचायत CSC की सफाई और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह मॉडल राजस्व सृजन को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव से जोड़ता है।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

vi. आंध्र प्रदेश कर रहा प्लास्टिक का वाणिज्य वस्तु के रूप में उपयोग



गैर-पृथक सूखे कचरे की डंपिंग से निपटने के लिए गुंटूर में 2025 में शुरू किए गए इस मॉडल के माध्यम से ग्रामीण लोग 'स्वच्छ रथम' के जरिए अलग-अलग, साफ किए गए सूखे कचरे का प्रदान दाल, आटा, डिटरजेंट आदि जैसी पसंदीदा दैनिक उपभोग की सामग्रियों के बदले करते हैं।

'स्वच्छ रथ सारथी (SRS)' लोगों से सूखे कचरे की खरीद करता है और इसे नामित स्क्रेप डीलर स्वच्छ बंधु को बेचता है। इस दृष्टिकोण से प्लास्टिक कचरे को कम करते हुए और चक्रीय अर्थव्यवस्था में सहायता करते हुए स्रोत पृथक्करण के माध्यम से व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। SRS को ग्राम पंचायत निधि से लगभग 25,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक मिलता है।

700 से अधिक वाहन हैं जो 660 मंडलों और 53 बड़ी ग्राम पंचायतों को कवर करते हैं। प्रत्येक वाहन प्रति माह न्यूनतम 25 दिनों के लिए संचालित होता है।

प्रसंस्करण के लिए, सभी संग्रहण वाहनों को मौजूदा ठोस कचरा प्रसंस्करण केंद्र (SWPC) से मैप किया जाता है, जो आगे सहबद्धता सुनिश्चित करता है। इस एकत्रित कचरे को उठाने के लिए औपचारिक पुनर्चक्रण उद्योगों के साथ सहबद्धता की गई है।



घ. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बदलाव की कहानियां

vii. राजस्थान का बर्तन बैंक: एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करना



राजस्थान ने SBM(G) के तहत बर्तन बैंक मॉडल के माध्यम से एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिए एक अमूल्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। नागौर जिले के भेरंडा ब्लॉक में मोरी कालां ग्राम पंचायत में मार्च 2025 में शुरू किए गए इस मॉडल में ग्राम पंचायत स्तर पर स्टील के बर्तनों का एक बैंक बनाना शामिल है। प्लेट, गिलास, कटोरे, चम्मच और अन्य वस्तुओं से युक्त इन बर्तनों को सामुदायिक कार्यक्रमों, बैठकों और सामाजिक समारोहों के दौरान मामूली दरों पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। बर्तन बैंक का संचालन और रखरखाव राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय स्वामित्व और नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित करता है।

इस पहल को अपने पायलट चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। डिस्पोजेबल वस्तुओं के लिए एक सुलभ विकल्प प्रदान करके, मॉडल सीधे एकल-उपयोग प्लास्टिक की चुनौती का समाधान करता है, खासकर शादियों और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे बड़े आयोजनों के दौरान। यह टिकाऊ व्यवहारों की ओर बदलाव में सहायता करता है और समुदायों को दैनिक तथा सामाजिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में पुनः प्रयोज्य समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस मॉडल को अब राज्य भर में कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से विधायक निधि के माध्यम से और 530 ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। यह एक लागत प्रभावी और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है जिसे एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी को बढ़ावा देने और टिकाऊ-सक्षम अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।



क्या आप बूझ सकते हैं SBM(G) शब्दावली?

प्रत्येक संकेत को समझें और सही शब्द लिखें।

01

मैं ODF के बाद वह अगला चरण हूँ, जिसमें गांव अपशिष्ट प्रबंधन और दृश्यगत स्वच्छता के माध्यम से स्वच्छता परिणामों को बनाए रखते हैं।

उत्तर: _____

02

मैं जैविक कचरे को बायोगैस और स्लरी जैसे उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करता हूँ, कचरे से कंचन को बढ़ावा देता हूँ।

उत्तर: _____

03

मैं रसोई और स्नानघर से उत्पन्न ऐसा अपशिष्ट जल हूँ जिसे गांवों में उचित प्रबंधन की आवश्यकता है।

उत्तर: _____

04

मैं ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता की योजना बनाने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार स्थानीय संस्था हूँ।

उत्तर: _____

05

मैं कचरे की छंटाई करने की प्रक्रिया हूँ ताकि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके।

उत्तर: _____

06

मैं मात्र एक कार्य नहीं हूँ, बल्कि मिशन द्वारा प्रचारित एक दैनिक आदत और महत्वपूर्ण बात हूँ।

उत्तर: _____

07

मैं सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान सम्मान और संरक्षा सुनिश्चित करती हूँ।

उत्तर: _____

08

मैं गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रहण, पृथक्करण और उचित पुनर्चक्रण से निपटता हूँ।

उत्तर: _____

09

मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि समय के साथ गांव खुले में शौच से मुक्त बना रहे।

उत्तर: _____

10

मैं स्वच्छता को लोगों के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ जिसमें सभी शामिल हैं।

उत्तर: _____

10 जन आंदोलन
09 ODF स्थिरता
08 स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन
07 संरक्षा

06 स्वच्छता
05 पृथक्करण
04 ग्राम पंचायत

03 गांव जल
02 गांव स्वच्छता
01 ODF Plus

उत्तर:



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI

सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर



स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए,
हर महीने की 15 तारीख से पहले अपने विचार साझा करें sbmiec.ddws@gmail.com



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फ़ोन: 011-24362192 | ईमेल: js-sbm@gov.in